

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2002—अग्रहायण 22, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग), (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-02-29/2002/1-8.—श्री आर. के. श्रीवास्तव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग तथा खनिज साधन विभाग, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्रम, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री के विशेष सहायक के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 1552/2002/1-8/स्था.—श्री बी. पी. एस. नेताम, उप- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 18-11-2002 से 30-11-2002 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश अवधि में श्री नेताम को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार

देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

3. अवकाश से लौटने पर श्री नेताम को पुनः उप-सचिव के पद पर स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ किया जाता है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री नेताम यदि अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, स्कूल शिक्षा के पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ 5-1/2001/1/6.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 240/264/2001/1/6, दिनांक 15-10-2001 के अनुक्रम में ग्राम अचानकगार थाना कोटा जिला बिलासपुर में घटित घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में दिनांक 18-11-2002 से दो माह की अवधि की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 2804/1910/2002/2/एक.—श्रीमती निधि छिब्बर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को इस विभाग के पत्र क्रमांक 2363/1910/2002/2/एक, दिनांक 6-9-2002 द्वारा दिनांक 7-9-2002 से 13-9-2002 (7 दिवस) तक का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया था, इसी अनुक्रम में श्रीमती छिब्बर का दिनांक 14-9-2002 से 19-9-2002 (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इस विभाग के आदेश दिनांक 6-9-2002 में उल्लेखित कालम क्रमांक 2 से 5 यथावत रहेंगे।

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 2812/ 2307/ साप्रवि/ 02/1/ आ. ए. एस./लीव.—श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, राजस्व विभाग को, दिनांक 13-12-2002 से 18-1-2003 (37

दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही विदेश यात्रा (कनाडा एवं अमेरिका) की अनुमति भी दी जाती है। दिनांक 19-1-2003 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति स्वीकृत है।

2. श्री बी. के. एस. रे, को अवकाश से वापिस आने पर पुनः प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

3. अवकाश काल में श्री बी. के. एस. रे, को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि वे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक डी/8151/2026/21-अ (स्था.) छ. ग./2002.—राज्य शासन, श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में अतिरिक्त सचिव के पद पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5855/दो-2-101/2001/गोपनीय/2002, दिनांक 13-11-2002 के अनुपालन में अन्य आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2002

क्रमांक 8258/डी-2740/21-ब/छ. ग./2002.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5857/11-2/16/2001, दिनांक 13-11-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्री पी. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की सेवायें अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर

को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक 3989/3527/2002/सत्रह.—राज्य शासन एतद्वारा जांजगीर (चांपा) के नये जिला चिकित्सालय का नामकरण तत्काल प्रभाव से "बैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल जिला चिकित्सालय" करता है.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 4052/582/एम/2002/17.—राज्य शासन एतद्वारा शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुर्ग का नामकरण "मोहनलाल बाकलीवाल शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय" की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार धुब, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक 2783/1652/02/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व) कोरबा के बायलर क्रमांक एम. पी./3198 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 29-10-2002 से दिनांक 28-12-2002 तक के लिये दो माह की छूट देता है :—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के

दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक 2784/1652/02/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व) कोरबा के बायलर क्रमांक एम. पी./3224 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 9-10-2002 से दिनांक 8-12-2002 तक के लिये दो माह की छूट देता है :—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो वह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक F 6-2/2002/(6)/11.—राज्य शासन एतद्वारा राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (State Level Export Promotion Committee) का गठन आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार करता है :—

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सदस्य वित्त विभाग.
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सदस्य वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग सदस्य
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग. सदस्य
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी. सदस्य
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग. सदस्य
8. संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, सदस्य मुंबई.
9. संयुक्त सचिव (राज्य प्रकोष्ठ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली.

10. महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, सदस्य भोपाल.

11. महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, रायपुर.

12. अध्यक्ष, कान्फेडरेशन आफ इन्डियन इण्डस्ट्रीज वाणिज्य एवं उद्योग (राज्य प्रकोष्ठ) नई दिल्ली, स्टेट सेल, भिलाई.

13. अध्यक्ष, कान्फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, स्टेट सेल, रायपुर.

14. अध्यक्ष, पी. एच. डी. चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, स्टेट सेल, रायपुर.

15. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर. सदस्य सचिव.

2. मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में अपर मुख्य सचिव राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की अध्यक्षता करेंगे.

3. अध्यक्ष की अनुज्ञा से आवश्यकतानुसार ज्यादा सदस्य सहयोग करेंगे अथवा विशेष आमंत्रितों के रूप में बुलाये जा सकेंगे.

4. राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास को होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन, विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2002

क्रमांक 3776/1866/ज.सं./2002.—श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, सहायक यंत्री के पद पर जब मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर के अंतर्गत पदस्थ थे, तब इनके विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण अपनाकर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर द्वारा इनके श्यामनगर, रायपुर स्थित निवास पर दिनांक 2-11-1995 को तलाशी के दौरान ज्ञात

आय से स्रोतों से काफी अधिक अनुपातहीन संपत्ति पाये जाने के कारण क्र. 0/95 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया, तद्धार पर धाना विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल में अपराध क्रमांक 120/95 पंजीबद्ध किया गया।

2. विवेचना/जांच हेतु चेक अवधि दिनांक 1-1-1981 से दिनांक 2-11-1995 की अवधि निर्धारित की गई, विवेचना उपरांत प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों से यह बात प्रमाणित हुई कि आलोच्य अवधि के पूर्व अर्थात् दिनांक 6-2-1980 से दिनांक 31-12-1980 तक आरोपी की कुल आय 7282/- रु. एवं व्यय 4369/- रु. पाया गया, उक्त आय में से व्यय घटाने पर 2913/- रु. शेष बचते हैं, जो कि आरोपी की चेक अवधि के पूर्व की बचत है। आलोच्य अवधि (दिनांक 1-1-1981 से 2-11-1995 तक) में आरोपी की कुल आय समस्त ज्ञात स्रोतों से कुल रुपये 6,60,577/- एवं आलोच्य अवधि के पूर्व की बचत राशि रुपये 2913/- जोड़ने पर कुल आय रु. 6,63,490/- होती है, जबकि आरोपी द्वारा इस अवधि में रुपये 17,78,377/- व्यय किये गये। कुल व्यय रुपये 17,78,377/- में से कुल आय रुपये 6,63,490/- घटाने पर रुपये 11,14,847/- शेष बचते हैं, जो कि आरोपी द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्ति है, जिसके संबंध में श्री शर्मा द्वारा कोई संतोषजनक तथ्य/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा आदेश क्र. 8/50/2000/ पं. क्र. 534/21-क (अभि.), दिनांक 27-5-2000 से श्री शर्मा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित किये गये, उक्त आदेश की प्रत्याशा में लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 30-6-2000 को मान. विशेष न्यायालय, रायपुर में चालान प्रस्तुत किया गया, चालानी कार्यवाही के फलस्वरूप श्री शर्मा को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 3328351 (473), दिनांक 12 जुलाई 2000 द्वारा निलंबित किया गया।

4. माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर द्वारा विशेष दौंडिक प्रकरण क्र. 10/2000 विरुद्ध श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा, सहायक यंत्री प्रकरण में निर्णय दिनांक 30 अप्रैल 2002 के द्वारा श्री शर्मा को अवैध साधनों से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी आरोप प्रमाणित मानते हुए धारा 13 (1) ई, सहपठित धारा 13 (2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये जाने के साथ ही अनुपातहीन संपत्ति रुपये 4,97,750/- अपील अवधि के पश्चात् राजसात किये जाने के आदेश पारित किये गये। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि श्री शर्मा का कृत्य जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध पाया गया है, शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है तथा यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल

सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आता है।

5. मान. विशेष न्यायालय, रायपुर के निर्णय दिनांक 30-4-2002 की प्रत्याशा में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 (9) के अंतर्गत श्री डी. पी. शर्मा, सहायक यंत्री के विरुद्ध "सेवा से पदच्युत किये जाने जो कि मामूली तौर पर भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी" की शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधानिक निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-6-2/98/3/1, दिनांक 26-5-1998 के अनुसार उक्त शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है, अर्थात् दंडादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है।

6. चूंकि श्री शर्मा, सहायक यंत्री, राजपत्रित वर्ग-2 के अधिकारी हैं, अतः अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर का अभिमत प्राप्त किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1115/166/2002/जी.एस./दिनांक 17 अक्टूबर 2002 से राज्य शासन द्वारा लिये गये प्रावधानिक निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई है।

7. अतः राज्य शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया है कि श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, सहायक यंत्री को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 19 (1) एवं सहपठित नियम, 10 (9) के अंतर्गत शासकीय सेवा से पदच्युत किये जाने के दंड से दंडित किया जाता है, जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी।

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2002

क्रमांक 3780/880/ज. सं./2001.—श्री के. के. शुक्ला, जब सहायक यंत्री के पद पर रायपुर में पदस्थ थे, तब इनके विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा लोक सेवक के पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण अपनाकर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के संबंध में अपराध क्र. 12/93 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया, तथा दिनांक 4-2-93 को इनके शैलेन्द्रनगर रायपुर स्थित निवास गृह की तलाशी ली गई, जांच हेतु चेक अवधि दिनांक 1-1-81 से 5-2-93 निर्धारित की गई। विवेचना उपरांत प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों से यह बात प्रमाणित हुई कि चेक अवधि में आय के समस्त ज्ञात स्रोतों से कुल रु. 10,30,120/- की आय हुई, जबकि उसने इस अवधि में 18,54,293/- रु. की राशि व्यय/निवेश की, इस प्रकार आरोपी के पास रुपये 8,24,173/- की अनुपातहीन संपत्ति होना पाया गया, जिसके संबंध में श्री शुक्ला द्वारा कोई संतोषप्रद तथ्य/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. प्रकरण में म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा आदेश क्र. 8/279/96/21-क (अभि.), दिनांक 31-10-1996 से श्री शुक्ला के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित किये गये, उक्त आदेश की प्रत्याशा में लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 20-11-96 को मान. विशेष न्यायालय, रायपुर में चालान प्रस्तुत किया गया, चालानी कार्यवाही के फलस्वरूप श्री शुक्ला को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3328351 (343), दिनांक 1-1-1997 द्वारा निलंबित किया गया.

3. मान. विशेष न्यायालय, रायपुर द्वारा विशेष दंडिक प्रकरण क्र. 9/96 विरुद्ध श्री के. के. शुक्ला, सहायक यंत्री प्रकरण में निर्णय दिनांक 19-4-2002 के द्वारा श्री शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी आरोप प्रमाणित मानते हुए धारा 13 (1) ई, सहपठित धारा 13 (2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 5,000/- अर्थदंड से दंडित किये जाने के साथ ही अनुपातहीन संपत्ति रु. 5,72,761/- राजसात किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि श्री शुक्ला का कृत्य जिसके लिए इन्हें दोषसिद्ध माना गया है, शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है तथा यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आता है.

4. माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर के निर्णय दिनांक 19-4-2002 की प्रत्याशा में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-10 (9) के अंतर्गत श्री के. के. शुक्ला, सहायक यंत्री के विरुद्ध "सेवा से पदच्युत किये जाने, जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी" की शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधानिक निर्णय लिया गया है. म. प्र. शासन. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-6-2/98/3/1, दिनांक 26-5-1998 के अनुसार उक्त शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है, अर्थात् दंडादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है.

5. चूंकि श्री शुक्ला, सहायक यंत्री राजपत्रित वर्ग-2 के अधिकारी हैं, अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1114/162/2002/जीएस, दिनांक 17 अक्टूबर 2002 से राज्य शासन द्वारा लिये गये प्रावधानिक निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई है.

6. अतः राज्य शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया है कि श्री के. के. शुक्ला, सहायक यंत्री को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-19 (1) एवं सहपठित नियम-10 (9) के अंतर्गत शासकीय सेवा से पदच्युत किये जाने के दंड से दंडित किया जाता है, जो कि मामूली तौर पर शासन के

अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, अवर सचिव.

कृषि, विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक ए-1-ए/13/2002/14-1.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 90/2002, दिनांक 11-9-2002 के द्वारा निम्नलिखित उप संचालक, कृषि की सेवायें अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित पदों पर पदस्थ किया जाता है.

क्र.	अधिकारी का नाम	भारत शासन द्वारा जारी सूची का क्रमांक	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री बाल प्यासी	92	प्राचार्य, कृषक/ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, अजिरमा (अंबिकापुर).
2.	श्री पी. एन. सेंगर	93	प्राचार्य, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरावंड, जगदलपुर.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2002

क्रमांक ए-1-ए/14/2002/14-1.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 90/2002, दिनांक 11-9-2002 के द्वारा निम्नलिखित सहायक संचालक कृषि, राजपत्रित वर्ग-2 की सेवायें अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है.

क्र.	अधिकारी का नाम	भारत शासन द्वारा जारी सूची का क्रमांक	पदस्थापना कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डा. एन. के. दीक्षित	78	उप संचालक, कृषि, अंबिकापुर.
2.	श्री के. सी. गुप्ता	367	उप संचालक, कृषि, कवर्धा.
3.	श्री डी. पी. दीक्षित	375	उप संचालक, कृषि, जशपुर.
4.	श्री आर. के. राठौर	26	उप संचालक, कृषि, दुर्ग.
5.	कुमारी मनीषा वर्मा	31	आंचलिक प्रबंधक कृषि जलवायु क्षेत्रीय परि-योजना, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-9-65/गृह/2002.—सामान्य प्रशासन विभाग एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 एवं 24 जुलाई, 2002 को प्रश्न-पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्च स्तर
बस्तर-संभाग

1. श्री अरविन्द कुमार एका डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

बिलासपुर-संभाग

2. श्री फूलसिंह धुव डिप्टी कलेक्टर
3. कु. शाहला निगार सहायक कलेक्टर (सश्रेय).

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-9-65/गृह/2002.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2002 को प्रश्न-पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्च स्तर

रायपुर-संभाग

1. श्री राजेन्द्र कुमार श्रोती विकासखण्ड अधिकारी

बिलासपुर-संभाग

2. श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त.
3. श्री आर. बी. एस. डण्डोटिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
4. श्री भुवन लाल बंजारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :-

क्रमांक (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	स्तर (5)
----------------	------------	--------------	-------------------	-------------

बस्तर-संभाग

1. श्री समुद्र साय मुख्य कार्यपालन अधिकारी. द्वितीय उच्च स्तर
2. श्री कृष्ण कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी. भाग-ए उच्च स्तर पाबिया.

बिलासपुर-संभाग

3. श्री ललित शुक्ला जिला संयोजक द्वितीय उच्च स्तर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-9-70/गृह/2002.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जुलाई, 2002 को प्रश्न-पत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तक के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

सश्रेय
रायपुर-संभाग

1. श्री दिलीप कुमार अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
2. श्री साजिद मेमन परियोजना अधिकारी
3. श्रीमती उषा मिश्र पर्यवेक्षक

बस्तर-संभाग

4. श्री अशोक कुमार पाण्डे परियोजना अधिकारी
5. श्री महेश राम मरकाम परियोजना अधिकारी

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

6. श्रीमती सुनीता मण्डावी सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

बिलासपुर-संभाग

7. श्री आनंद प्रकाश किस्पोट्टा जिला महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
8. श्री अतुल दाण्डेकर बाल विकास परियोजना अधिकारी.
9. श्री मनोज कुमार बाल विकास परियोजना अधिकारी.
10. श्री सूर्यकान्त गुप्ता परियोजना अधिकारी
11. श्री तारकेश्वर प्रकाश सिन्हा परियोजना अधिकारी
12. कु. पुष्पा किरण कुजूर परियोजना अधिकारी

उच्च स्तर
बस्तर-संभाग

1. कु. विनीता भालवीय पर्यवेक्षिका
2. श्रीमती राजवन्ती साईमन पर्यवेक्षिका
3. श्रीमती प्रभादेवी शर्मा सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
4. श्रीमती प्रेमलता ठाकुर सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

बिलासपुर-संभाग

5. श्रीमती अरूणा यादव पर्यवेक्षिका
6. श्रीमती शशिप्रभा सोनी सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

(1)	(2)	(3)
7.	श्रीमती शीला एका	पर्यवेक्षिका
8.	श्रीमती प्रभा लकड़ा	परियोजना अधिकारी
9.	श्रीमती सुशीला बखला	परियोजना अधिकारी
10.	श्रीमती अलबिना कुजूर	बाल विकास परियोजना अधिकारी.

निम्न स्तर
रायपुर-संभाग

1.	श्रीमती कुन्ती कुशरे	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
----	----------------------	--

बस्तर-संभाग

2.	श्रीमती जैनी बघेल	पर्यवेक्षिका
3.	कु. श्याम भास्कर	पर्यवेक्षिका
4.	कु. फबियाना टोप्पो	पर्यवेक्षिका
5.	श्रीमती मीना जुरीं	पर्यवेक्षिका
6.	श्रीमती जोहत्तरीन गौतम	पर्यवेक्षिका
7.	श्रीमती भावना कोडोपी	पर्यवेक्षिका
8.	श्रीमती पुष्पा मरकाम	पर्यवेक्षिका
9.	श्रीमती कला पोया	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
10.	श्रीमती पार्वती शर्मा	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
11.	कु. शकीला बानो	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

(1)	(2)	(3)
बिलासपुर-संभाग		
12.	श्रीमती मोहिनी सिन्हा	पर्यवेक्षिका
13.	श्रीमती शांता सरोज एका	सहायक निर्देशिका
14.	श्रीमती फिलसिता लकड़ा	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
15.	श्रीमती मोतिन बाई कुरें	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
16.	श्रीमती एलिजाबेथ टोप्पो	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-9-78/02/गृह.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "सामान्य विधि प्रश्न-पत्र 2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

रायपुर-संभाग

1.	श्री आनंद कुदरया	वन क्षेत्रपाल
----	------------------	---------------

बिलासपुर-संभाग

2.	श्री अनिल कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल
----	----------------------	---------------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-3/163/2/गृह/2002.—राज्य शासन एतद्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला का विभाजन कर दिया गया है। विभाजन उपरान्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पदस्थ अधिकारियों को रासायनिक परीक्षक एवं सहायक रासायनिक परीक्षक (एक्स आफिशियल पोस्ट) की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 (4) के अंतर्गत निम्न अधिकारियों को रासायनिक परीक्षक एवं सहायक रासायनिक परीक्षक घोषित किया जाता है।

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	घोषित पदनाम (3)	संकाय (4)
1.	डॉ. एम. पी. गौतम, संयुक्त संचालक	रासायनिक परीक्षक	
2.	श्रीमती शुभ्रा गौतम, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	सहायक रासायनिक परीक्षक	बायोलॉजी
3.	श्री गिरवर सिंह साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	सहायक रासायनिक परीक्षक	भौतिकी
4.	डॉ. (श्रीमती) शेषा सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	सहायक रासायनिक परीक्षक	बायोलॉजी

Raipur, the 25th November 2002

No. F-3/163/2/Home/2002.—The State Government hereby makes division of the State Forensic Science Laboratory. The following officers posted at State Forensic Science Laboratory, Raipur, are hereby declared as Chemical Examiner and Assistant Chemical Examiner to the Government of Chhattisgarh respectively against their name under the provision of section 293 (4) Cr. P. C.

S. No. (1)	Name of Officer & Post (2)	Declared as (3)	Discipline (4)
1.	Dr. M. P. Goutam, Joint Director	Chemical Examiner	
2.	Smt. Shubhra Goutam, Senior Scientific Officer.	Assistant Chemical Examiner	Biology
3.	Shri G. S. Sahu, Senior Scientific Officer	Assistant Chemical Examiner	Physic
4.	Dr. (Smt.) Sesha Saxena Senior Scientific Officer.	Assistant Chemical Examiner	Biology

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक/490/अ.वि.अ./भू-अर्जन/9/अ-82 सन् 2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	बागबाहरा कला प. ह. नं. 119/67	1.11	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक/488/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2/अ-82 सन् 2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	अछोला प. ह. नं. 3/3	1.345	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	कोडार व्यपवर्तन योजना अंतर्गत अछोली सब माइनर एवम् अछोला सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक/489/अ.वि.अ./भू-अर्जन/1/अ-82 सन् 2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	नवागांवकला प. ह. नं. 118/65	6.695	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक/487/अ.वि.अ./भू-अर्जन/6/अ-82 सन् 2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	भालुचुंवा प. ह. नं. 109	51.45	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	चंडी डोंगरी जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक 7370/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	छिंदिया	0.64	कार्यपालन यंत्री, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बैकुण्ठपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) जिलाध्यक्ष, जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बायंग प. ह. नं. 5	0.989	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, रायगढ़.	मांड व्यपवर्तन योजना अंतर्गत रानीगुड़ा माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/29/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	करवाडबरी	1.976	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर भण्डारा जलाशय के करवाडबरी माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/31/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	रमतला	2.306	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर भण्डारा जलाशय के टाड़ापारा माइनर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/32/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	रमतला	1.571	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर भण्डोरा जलाशय के रमतला माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/683.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नन्देली प. ह. नं. 6	0.654	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सक्ती उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/684.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि का अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प. ह. नं. 6	3.003	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	रगजा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/685.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि का अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सेन्दरी प. ह. नं. 3	0.020	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	चमरा बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/686.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	चमरा बरपाली प. ह. नं. 13	1.758	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	चमरा बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/687.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मसनिया खुर्द प. ह. नं. 6	1.357	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	रीवांपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/688.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	करापाली प. ह. नं. 6	1.146	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	करापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/689.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प. ह. नं. 6	2.236	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	करापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/690.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प. ह. नं. 6	1.839	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया..	रगजा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/691.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नन्देली प. ह. नं. 7	1.405	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	बोरदा उप-वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/692.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्की	सिंघनसरा प. ह. नं. 10	3.355	कार्यपालन यंत्री, भिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	सिंघनसरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्की के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ एवं पदेन
अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2002

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—दुर्ग
(ख) तहसील—साजा
(ग) नगर/ग्राम—गाड़ाघाट, प. ह. नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर

क्रमांक प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
434	0.10
482	0.02
704	0.70

(1)	(2)	(1)	(2)
522	0.01	428/1	0.020
516	0.01	419	0.120
720	0.70	200	0.016
470	0.15	510/2	0.032
517	0.01	189	0.040
योग	1.70	428/2	0.124
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यप- वर्तन बंद पार व डूबान.		1610/2	0.020
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय साजा में देखा जा सकता है.		1610/1	0.056
		182	0.080
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.		443	0.012
		274	0.064
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग		402/5	0.081
		391	0.040
सरगुजा, दिनांक 12 नवम्बर 2002		450/1	0.044
रा. प्र. क्र./26/अ-82/2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		183	0.316
अनुसूची		402/3	0.048
(1) भूमि का वर्णन—		199	0.112
(क) जिला-सरगुजा		224/1	0.008
(ख) तहसील-अम्बिकापुर		392	0.140
(ग) नगर/ग्राम-रजपुरीकला		449	0.040
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.791 हेक्टेयर		184	0.016
		402/2	0.032
		219	0.040
		548/1	0.020
		406	0.120
		209	0.128
		508/1	0.016
		402/4	0.040
		योग	1.791
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-धुनघुट्टा परियोजना अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
(1)	(2)	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.	
405/1	0.222		

सरगुजा, दिनांक 12 नवम्बर 2002

रा. प्र. क्र./36/अ-82/2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-सुखरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
779/1	0.020
योग	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुखरी सब माइनर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 नवम्बर 2002

रा. प्र. क्र./37/अ-82/2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-श्रीगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

161/1

0.057

योग

0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बांकी परि-योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बनोरा/बेलरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.889 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

ग्राम बनोरा

908/2

0.068

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग
909/3	0.028	
909/12	0.028	
910/1 क	0.121	जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002
910/2	0.056	क्रमांक 714/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
911	0.113	
912	0.072	
योग	7	0.486

ग्राम बेलरिया

अनुसूची

229/1	0.028
235	0.097
236/1	0.153
237	0.028
238	0.097
योग	5
	0.403
बनौ 1	0.486
बलेरिया	0.403
कुल योग	0.889

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.963 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)
(1) (2)

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बनोरा, खैर-
पाली, बेलरिया मार्ग के 3/2 पर छोटी केलो सेतु पहुंच मार्ग हेतु
भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़
कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

583	0.081
576	0.053
575	0.045
1763	0.008
1775	0.024
573	0.040
572	0.032
538	0.081
537	0.069
1779	0.032
1778	0.008
536	0.036
528	0.032
523	0.032
522	0.065
521	0.036
518	0.024
510	0.089
517	0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
509	0.061	2575	0.008
508	0.069	3090	0.004
2000	0.069	3092	0.008
2462	0.105		
2467	0.049	योग	2.963
2499	0.053		
2498	0.053	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमगांव सब	
2508	0.032	माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.	
2510	0.097		
2517	0.036	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव	
2519	0.113	परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
2520	0.008		
2547	0.081		
2546	0.040	जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002	
2545	0.061		
2570	0.053	क्रमांक 715/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का	
2573	0.049	समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि	
2574	0.057	की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए	
2585	0.069	आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन्	
2584	0.113	1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत	
3075	0.004	इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन	
3076	0.016	के लिए आवश्यकता है :-	
3077	0.004		
3074	0.020	अनुसूची	
3085	0.016		
3073	0.004	(1) भूमि का वर्णन-	
3087	0.020	(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)	
3086	0.004	(ख) तहसील-डभरा	
3089	0.133	(ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 1	
3072	0.016	(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.712 हेक्टेयर	
3754	0.073		
3755	0.008	खसरा नम्बर	रकबा
3753	0.012		(हेक्टेयर में)
3752	0.012	(1)	(2)
3607/8, 9, 11, 10	0.162	314	0.020
3735	0.097	315	0.162
3741	0.004	316	0.525
3612/2	0.174	317	0.353
3734		308	0.494
3774/2	0.008	309	
3775	0.024	310	
2576	0.004	311	
2578	0.012		

(1)	(2)	(1)	(2)
312	0.045	351/1	0.040
307	0.040		
306	0.061	योग	47
305	0.109		8.712
345	0.635	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंधरा वितरक नहर हेतु.	
346	0.170	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.	
347	0.085		
342	0.089		
341	0.146		
350	0.996		
335	0.069		
334	0.137	जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002	
332	0.162		
331	0.049		
333	0.040		
349	0.065		
330/1	0.085		
330/2	0.057		
330/3	0.008		
329/2	0.012		
412	1.112		
413	0.162		
414			
415	0.267		
416	0.210		
417	0.530		
418	0.404		
419	0.193		
420	0.219		
429	0.299		
428	0.028		
421	0.369		
422	0.308		
423	0.020		
574	0.214		
573	0.214		
571	0.069		
572	0.097		
576	0.242		
575	0.089		
570	0.004		
577/1	0.008		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भाठटा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.111 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
429/2	0.069
430	0.331
431	0.940
432	0.052
437	0.299

(1)	(2)	(1)	(2)
439	0.420	578	0.065
		580	0.162
योग	2.111	589	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.		594	0.073
		593	0.032
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी; हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है,		595/2	0.004
		501	0.890
		505	
		597/4	
		577	0.040
जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002		480	0.065
		506	
क्रमांक 717/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		481	0.024
		479	0.053
		390/2	0.316
		390/1	0.004
		472	0.024
		389	0.180
		386	0.235
		330	0.130
		331/3	0.073
		358	0.061
		359	0.154
		360	0.069
		355	0.012
		354	0.045
		362	0.080
		363	0.089
		376/1	
		374	0.024
		365	0.048
		371	0.162
		671	
		369	0.080
		368	0.073
		664	0.150
		665	0.200
		661	0.004
		663	0.004
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	योग	
(1)	(2)	43	4.532
553/3	0.008		
566/1	0.089		
566/4	0.263		
565	0.012		
567/1	0.130		
568	0.154		
567/2	0.069		
569	0.012		
570	0.101		
579	0.069		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर हेतु.

(1)

(2)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

49/1

0.061

50/3

0.053

50/4

45/1

0.004

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

50/5

0.057

82

0.069

क्रमांक 718/सा-1/सात.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

80/1

0.073

88/1

0.004

79/2

0.040

78/2

0.049

76/1

0.085

94/1

0.065

110

0.061

111/2

0.036

112

0.004

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

130/1

0.344

(ख) तहसील-डभरा

133/1

0.081

(ग) नगर/ग्राम-करौद, प. ह. नं. 6

140

0.004

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.384 हेक्टेयर

139

0.101

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

144

0.049

(1)

(2)

146/1

0.206

147

148

149

150

151

0.004

194/1

0.045

194/2

0.008

195/1

0.004

195/2

योग

39

2.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

(1)

(2)

क्रमांक 719/सा-1/सात.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

204/2

0.069

204/3

0.049

237

0.182

236

0.004

अनुसूची

241/1

0.158

246

0.032

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

247/2

0.004

(ख) तहसील-डभरा

245

0.122

(ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 6

242

0.040

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.252 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

243

0.069

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

244

0.061

260

0.061

938/2

0.121

937/4

0.036

261

937/1

0.089

262

937/2

0.053

936/5

0.028

263

936/3

0.008

936/4

0.073

336/7

0.117

935/2

0.008

935/3

0.032

336/6

0.069

936/1

0.049

335/3

0.109

932/1

0.150

932/2

0.137

335/4

0.081

931

0.085

331/3

0.065

928/4

0.081

928/5

0.138

331/1

0.113

928/6

0.061

190/1

0.061

328/1

0.125

190/2

0.004

198

0.234

328/2

0.182

205/3

0.004

326/1

0.016

199/1

0.105

199/4

0.012

327

199/3

0.028

356/1

0.032

(1) (2) जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

356/2	0.101
324	0.053
322/2	
323/2	
356/3	0.045
357/2	0.016
357/1	0.016
320/3	0.133
322/1	
323/1	
321/2	0.315
321/1	
582/4	0.174
585/3	
582/5	
582/2	
581	0.181
582/1	0.069
576	0.210
579	
578	0.008
542	0.073
560/2	0.004
560/4	0.089
545	0.105
559	0.004
546/2	0.020
546/3	0.093
549	0.012
547/2	0.012
548	0.093
516/4	0.012
238	0.057

योग 5.252

क्रमांक 720/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सुखदा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.998 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
904/1	0.065
904/2	0.069
903/1	0.020
903/3	0.049
903/2	0.020
905	0.016
902/1	0.113
902/2	0.008
909/4	0.069
911/1	0.041
911/2	0.041
921	0.081
922/2	0.045
870/2	0.028
869/3	0.024
869/5	0.052
869/2	0.032
868	0.077
863/1	0.057
864/1	0.004
867/2	
862	0.069
861	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
851/1	0.085	1339/1	0.113
848/1	0.061	1339/2	0.004
848/2	0.081	1368/1	0.057
849/1	0.020		
839/1-7	0.012	योग	65 3.998
849/3			
850/2-3			
843/1	0.008	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंचरा वितरक	
843/2	0.008	नहर हेतु.	
844/1	0.121	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव	
844/2	0.004	परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.	
841/3	0.012		
981/2	0.081		
980/1	0.012	जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002	
980/2	0.012		
983	0.235	क्रमांक 721/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का	
1000/4	0.158	समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि	
1009/1	0.194	की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए	
1008/1	0.004	आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन्	
1008/2	0.077	1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत	
1009/4	0.117	इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन	
1310	0.109	के लिए आवश्यकता है :—	
1004	0.020		
1311	0.024	अनुसूची	
1312	0.063	(1) भूमि का वर्णन—	
1309	0.004	(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)	
1314	0.085	(ख) तहसील-डभरा	
1315	0.081	(ग) नगर/ग्राम-चुरतेली, प. ह. नं. 6	
1324/1	0.101	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.383 हेक्टेयर	
1324/2	0.077		
1324/3	0.061	खसरा नम्बर	रकबा
1325/2	0.101		(हेक्टेयर में)
1325/3	0.101	(1)	(2)
1325/4	0.012		
1336/1	0.061	612/1	0.024
1344	0.202	613/1	0.223
1343	0.048	613/2	0.040
1342	0.052	653	0.113
1341	0.008	654	0.032
1338	0.129	655/3	0.040
1340/1	0.081	655/1	0.065
1340/3	0.061	655/8	0.004

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
662	0.024		
663	0.117		
665/3	0.008	93/1	0.057
665/1	0.040	93/2	0.065
668/2	0.036	92	0.089
666/2	0.024	88	0.061
667/2	0.125	87	0.061
667/5		89	0.004
694/1	0.032	90	0.016
655/4	0.101	86	0.040
692	0.206	4/1	0.032
691		9	0.020
690		8	0.121
688/2	0.101	7	0.109
689/2		14	0.069
687/1	0.028	24/1	0.134
		23	0.130
योग	20	22	0.040
	1.383	24/2	0.057
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर.		24/4, 5	0.061
		27/3	0.113
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.		27/2	0.101
		27/1	0.146
		योग	21
			1.526

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 722/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.526 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 723/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1)

(2)

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.565 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1477/2 ख 0.024

1477/2 ग 0.162

1476/2 0.040

1477/2 घ 0.085

1479/2 0.024

1477/2 ढ 0.080

1477/2 उ 0.129

1479/3 0.073

1477/2 ट 0.222

1479/4 0.032

1480/2 0.251

1659/2 0.057

1659/1 0.049

1657/6 0.057

1657/8 0.032

1660/2 0.089

1662/1-3 0.089

1662/2-4 0.016

1660/3 0.154

1663 0.069

1684 0.121

1683/1 0.032

1673/1 0.061

1672 0.137

2224/1 0.065

2227 0.004

2233 0.105

2232 0.081

2324/3 0.081

2324/1 घ 0.364

2334/1 0.141

2334/2

2339

0.121

2348

0.081

2349/2

0.113

2351/1

0.049

2362/1

0.081

2362/2 ख

0.040

2364

0.049

2365

0.081

2366/1

0.016

1661

0.004

2367/2

0.004

योग

42

3.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंधरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 724/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-रामभांटा, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.507 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
		1032/1	0.032
		1032/2	0.081
949/1	0.020	1032/3	0.049
949/2	0.020	1032/4	0.032
950/1	0.040	844	0.004
950/4	0.008	845	0.344
951	0.069	839	0.008
952	0.012	836	0.658
953	0.089	846	
941/1	0.016	837	0.008
959	0.077	834	0.024
963	0.053	833	0.365
962	0.089	825	0.191
961	0.101	824	0.133
931	0.073	823	0.210
928	0.040	822	0.236
929	0.125	955	0.146
927/1	0.109	991	
927/2	0.061	योग	55 5.507
934/1	0.069		
934/2	0.012		
925	0.073		
926	0.061		
935	0.020		
936	0.061		
924	0.081		
921	0.016		
920	0.024		
922	0.150		
923	0.129		
893	0.081		
919	0.206		
892	0.069		
894	0.640		
891	0.016		
870	0.032		
871			
869	0.008		
873	0.130		
859	0.073		
842	0.029		
843	0.004		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 725/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ठनगन प. ह. नं., 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.536 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
		414/1	0.012
		262	0.004
874/1	0.040	260	0.032
872/1	0.050	259	0.004
857	0.004	263	0.004
856/2	0.004	243	0.109
856/1	0.190	244	0.012
856/4	0.012	228	0.012
320/1	0.125	237	0.040
319	0.109	238	0.040
317	0.050	240	0.070
326	0.100	236/2	0.095
327/2	0.060	236/3	0.150
327/1	0.050	236/4	
328	0.069		
329	0.095	योग	
333	0.127	51	2.536
332/4	0.028		
338/1	0.035		
338/2	0.008		
340	0.010		
337	0.090		
343	0.170		
346/1	0.050		
345/2	0.060		
346/2			
336	0.004		
239	0.004		
281	0.008		
282	0.061		
283/3			
284/2	0.053		
204	0.004		
280	0.040		
505/3	0.020		
254	0.004		
279	0.045		
278	0.070		
277	0.035		
505	0.004		
257	0.004		
261	0.060		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंघरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व
विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र./1/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)		(1)	(2)
(ख) तहसील-कोटा			
(ग) नगर/ग्राम-मटसगर			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर			
योग		1	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लोक निर्माण विभाग के सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(क) जिला-बिलासपुर		(1)	(2)
(ख) तहसील-मुंगेली			
(ग) नगर/ग्राम-कामता, प. ह. नं. 6			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.886 हेक्टेयर			
योग		4/1 क	0.109

(1)

(2)

4/1 ख	0.101
7/2	0.097
7/3	0.093
7/4	0.045
7/7	0.141
7/8	0.121
7/9	0.477
7/13	0.218
10	0.109
12	0.016
6	0.324
7/1	
8/2	0.032

योग 12 1.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगरा उपपर्वत योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(क) जिला-बिलासपुर		(1)	(2)
(ख) तहसील-मुंगेली			
(ग) नगर/ग्राम-झगरहट्टा, प. ह. नं. 9			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.491 हेक्टेयर			
योग		12/1	0.364

(1)	(2)
113/1	0.197
13	0.249
9/3	0.041
14	0.405
24	0.016
25	0.024
6	0.221
113/2	0.004
112/15	0.121
112/17	0.073
112/16	0.041
112/4	0.041
112/13	0.012
112/9	0.053
112/7	0.041
123/2	0.012
112/5	0.053
112/6	
122/1	0.032
122/2	0.032
121/2	0.049
121/4	
123/1	0.105
126	0.305
योग	2.491

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-सुरेठा, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.862 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1/1

0.004

11/4

0.105

13

0.186

16

0.121

19

0.057

18/1

0.073

18/4

0.065

35/6

0.243

20/1

0.008

योग

9

0.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगरा
व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगरा
व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-हेडसपुर, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	1/2	0.137
129/2	0.065	113/1	0.073
130/2		114/1	
130/3	0.106	115	
110/2	0.065	113/3	0.081
131/1	0.073	114/3	
131/2	0.024	117	0.283
129/3	0.028	206	0.214
130/4		122	0.032
129/1	0.024	124	0.129
130/1		127	0.004
		128	
योग	7	129	0.061
	0.388	188	0.016
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगरा		185	0.178
व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.		186	
		187	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		181	0.020
(राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.		182	
		183	
बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002		159	0.065
क्रमांक 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात		292/3	0.049
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		320	0.024
भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के		173	0.057
लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित		170/1	0.016
क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित		170/2	0.081
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता		169/1	
है :—		169/2	0.089
		174	0.032
		167	0.057
		168/1	0.032
		168/2	0.028
		291	0.101
(1) भूमि का वर्णन—		292/2	0.089
(क) जिला-बिलासपुर		319	0.065
(ख) तहसील-मुंगेली		313	0.024
(ग) नगर/ग्राम-रामाकापा, प. ह. नं. 8		310	0.061
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.627 हेक्टेयर		314/6	0.093
खसरा नम्बर	रकबा	314/3	0.137
(1)	(2)	302/1	0.105
		302/3	0.129
1/1	0.016	315	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
317	0.032	97/11	0.032
		116/2	0.040
योग 35	2.627	97/13	0.032
		117	0.081
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगरा		118/1	0.105
व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.		153/1	0.157
		152/2	0.105
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		151	0.133
(राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.		47/14	0.129

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 11/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-करूपान उर्फ बामपारा, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.733 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

33/1	0.133
115/2	0.028
153/2	0.024
153/6	0.065
47/3	0.097
47/7	0.129
47/4	0.137
47/8	
97/3	0.077
97/14	0.061
98/3	0.061
97/12	0.081
97/10	0.020

योग	21	1.733
-----	----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 12/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-करूपान, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.287 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217/4	0.105

(1)	(2)	(1)	(2)
217/2	0.097	126/2	0.073
218/11	0.133	125	0.121
218/27		124/1	0.057
218/10	0.125	101/3	0.073
234/1	0.226	101/4	0.069
234		101/5	0.073
234/2	0.121	101/2	0.089
235	0.105	156/3	0.089
236/4	0.016	101/6	0.073
230	0.186	156/10	0.174
229/3	0.121	162/2	0.020
229/1	0.012	156/5	0.093
229/2	0.036	159/1	0.251
योग	12	169/13	0.040
	1.287		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 13/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-टेमरी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.340 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
126/1	0.045

योग 15 1.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 14/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.421 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.461
23/2	0.153
23/1	0.194
24	
20/1	0.065
146/2	0.137
21	0.081
146/1	0.065
127/2	0.049
120	0.089
123	
145	
25/1	0.161
25/3, 28	0.527
26/1	
29/1, 30/2	
128/2	0.089
134/2	0.004
30/2 ग	0.024
30/2 घ	0.032
30/2 ङ	0.121
144/1	0.032
127/3	0.073
144/2	0.032
129	0.020
130	0.008
योग	21 2.421

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 15/अ-82/2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-चातरखार, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76/1	0.016
77/1	0.081
463/1	0.153
योग	3 0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 16/अ-82/2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-झगरहट्टा, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.271 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
		64/5	0.016
		41/1	0.061
178/8, 9	0.032	41/2	0.234
178/10	0.020	42	0.275
178/1	0.077	43	0.016
178/2	0.045		
178/5, 6	0.097	योग	9 1.004
योग	5 0.271		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 17/अ-82/2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-करूपान, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.004 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/2	0.016
58	0.129
59/1	0.129
59/2	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 19/अ-82/2001-2002.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
181/1	0.194
185	
186/1	0.069
206/1	0.069
205/1	0.089
205/2	0.032
211/11	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
211/10	0.113	307	0.077
211/15	0.279	329/1	0.243
211/14	0.012	302	0.057
214	0.429	211/4	0.024
215			
216/1		योग	24 2.469
294	0.016		
299/2	0.097	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.	
299/4			
293	0.121		
299/5	0.113	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
292/1	0.049		
303/4	0.125		
303/1	0.129		
304/1		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
303/6	0.061		

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, साक्षरता मार्ग अंबिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

अंबिकापुर, दिनांक 11 नवम्बर 2002

क्रमांक 15/2002.—म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (25 सन् 1958) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में धारा 13 (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्ति जो कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक श्रम/4/रायपुर, दिनांक 20-3-2002 द्वारा श्रम पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, और चूंकि जैसा कि श्रम पदाधिकारी कार्यालय सरगुजा के क्षेत्रांतर्गत स्थित बैकुण्ठपुर (औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र तथा ऐसी स्थानीय सीमा से तीन किलोमीटर तक का क्षेत्र) जहां पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ/28-132-99-सोलह-ए भोपाल के 3 मार्च, 2000 द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम को प्रभावशील किया है. अतः उक्त धारा 13 (3) (क) के तहत बंद दिवस (क्लोज डे) नियत किया जाना अनिवार्य है.

अतः एतद्वारा मैं, बी. एस. बरिहा, श्रम पदाधिकारी, अंबिकापुर उपरोक्त वर्णित स्थापनाओं में जो दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 में परिभाषित है, के लिए वाणिज्यिक संघों की मांग तथा अधिनियम को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए लोकहित में सप्ताह के एक दिन "शनिवार" को बंद दिवस (क्लोज डे) नियत करता हूं. तथा एतद्वारा निर्देश जारी करता हूं कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से समस्त संस्थानों पर प्रभावशील माना जावेगा.

बी. एस. बरिहा,
श्रम पदाधिकारी.